



19 मिनट	8	24	5 + 1	GS1 - 4	GS2 - 22	GS3 - 32
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	MCQS + MAINS	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 राजनाथ सिंह ने HSL में FSS-1 लॉन्च किया और FSS-5 के लिए कील रखी

क्यों जरूरी: समुद्री बुनियादी ढांचा और जहाज निर्माण: आत्मनिर्भरता और ब्लू-वॉटर नेवी (Blue-water navy) क्षमताओं पर एक GS3 केस स्टडी।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

2 पॉपुलेशन सेंसस 2027 का डेटा अगले साल मार्च या अप्रैल तक आएगा

क्यों जरूरी: मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने घोषणा की है कि जनसंख्या जनगणना 2027 का प्रोविजनल डेटा (provisional data) मार्च या अप्रैल 2027 तक उपलब्ध हो जाएगा।

GS1 • भारतीय समाज

P

M

3 DRDO ने किया स्वदेशी HAPS प्लेटफॉर्म का सफल टेस्ट, 21 किमी की ऊंचाई तक पहुंचा

क्यों जरूरी: DRDO ने एक स्वदेशी हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (HAPS) का सफल परीक्षण किया है, जो 21 किमी की ऊंचाई तक पहुंच गया।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

4 केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की निगरानी करने और बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है

क्यों जरूरी: केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की निगरानी करने और बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है।

GS2 • राज्यव्यवस्था एवं संविधान

P

M

5 वर्ल्ड बैंक ने भारत की FY27 GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया

क्यों जरूरी: वर्ल्ड बैंक ने अपने नवीनतम 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में भारत की वित्त वर्ष 2027 (FY27) की GDP विकास दर के अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

आज का आँकड़ा

₹1,969 करोड़

2025-26 में HSL द्वारा दर्ज किया गया प्रोडक्शन वैल्यू
(Production value)।

स्टैटिक से जोड़ें

42nd Amendment

प्रस्तावना (Preamble) में 'socialist' और 'secular' शब्द जोड़े गए। खबर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के दर्शन के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को महत्वपूर्ण बताया।

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

राजनाथ सिंह ने HSL में FSS-1 लॉन्च किया और FSS-5 के लिए कील रखी

चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना की समुद्री पहुंच को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) में 43,500 टन वाले FSS-1 को लॉन्च किया और FSS-5 के लिए कील रोधी (Keel laying) की प्रक्रिया शुरू की।

याद रखें

- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) — 45,000 डेडवेट टन तक के जहाज बनाने वाला यार्ड।
- Fleet Support Ship (FSS) — वह जहाज जिसे समुद्र में युद्धपोतों को ईंधन भरने और रसद की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ₹1,969 करोड़ — 2025-26 में HSL द्वारा दर्ज किया गया प्रोडक्शन वैल्यू (Production value)।

मेन्स कोण भारत के समुद्री क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' पहल और समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में, एचएसएल (HSL) जैसी घरेलू जहाज निर्माण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131759

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

DRDO ने किया स्वदेशी HAPS प्लेटफॉर्म का सफल टेस्ट, 21 किमी की ऊंचाई तक पहुंचा

चर्चा में क्यों: DRDO ने एक स्वदेशी हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (HAPS) का सफल परीक्षण किया है, जो 21 किमी की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह भारत की हवाई निगरानी और संचार क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

याद रखें

- ADRDE: एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (Aerial Delivery Research and Development Establishment) आगरा में स्थित है।
- HAPS: High-Altitude Platform (HAPS) एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है जिसका परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है।
- फ्लाइट टेस्ट के दौरान प्लेटफॉर्म ने 21 किमी की अधिकतम ऊंचाई (peak altitude) हासिल की।

मेन्स कोण भारत की सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक निगरानी और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में स्वदेशी उच्च-ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म (HAPS) तकनीक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131718

GS1 · भारतीय समाज

P

M

पॉपुलेशन सेंसस 2027 का डेटा अगले साल मार्च या अप्रैल तक आएगा

चर्चा में क्यों: मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने घोषणा की है कि जनसंख्या जनगणना 2027 का प्रोविजनल डेटा (provisional data) मार्च या अप्रैल 2027 तक उपलब्ध हो जाएगा।

याद रखें

- लद्दाख 2027 के लिए पूरे जनगणना (Census) कार्य को पूरा करने वाला पहला क्षेत्र है।
- 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना (digital Census) होगी।
- Census 2027 में पहली बार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा अन्य जातियों की गणना (caste enumeration) भी शामिल की जाएगी।

मेन्स कोण भारत के सामाजिक-आर्थिक नियोजन के संदर्भ में डिजिटल जनगणना की ओर संक्रमण और 2027 की जनगणना में जातिगत गणना के समावेश के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131729

GS2 · राज्यव्यवस्था एवं संविधान

P

M

केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की निगरानी करने और बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है

चर्चा में क्यों: केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की निगरानी करने और बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है।

याद रखें

- ITLA: इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (Integrated Transport and Logistics Authority)।
- ITLA अप्रैजल थ्रेशोल्ड (Appraisal threshold): ₹500 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाले प्रोजेक्ट्स।
- ITLA का मंडेट: सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स, शिपिंग, एविएशन, वॉटरवेज़ और अर्बन मोबिलिटी की निगरानी करना।

मेन्स कोण भारत में बहु-मोडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की बाधाओं की चुनौतियों को दूर करने में 'इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' (ITLA) जैसी एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की स्थापना किस प्रकार सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131558

वर्ल्ड बैंक ने भारत की FY27 GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया

चर्चा में क्यों: वर्ल्ड बैंक ने अपने नवीनतम 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में भारत की वित्त वर्ष 2027 (FY27) की GDP विकास दर के अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है।

याद रखें

- वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत के FY27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान: 7.1 प्रतिशत।
- भारत की FY26 GDP ग्रोथ: 7.8 प्रतिशत।
- FY27 में इन्फ्रास्ट्रक्चर गुड्स ग्रोथ: 7.2 प्रतिशत।

मेन्स कोण वैश्विक व्यापार तनाव और मानसून की कमी के बावजूद भारत की निरंतर जीडीपी वृद्धि को गति देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131478

RBI से बेंचमार्क रेपो रेट 5.50% करने की उम्मीद

चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 प्रतिशत के करीब पहुंच रही महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए बेंचमार्क रिपर्चेज रेट (Repurchase Rate) को बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने की उम्मीद है।

याद रखें

- बेंचमार्क रिपर्चेज रेट (Benchmark repurchase rate) — इसे बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने की उम्मीद है।
- महंगाई — 5 प्रतिशत के करीब।
- तेल की कीमतें — \$100 प्रति बैरल से अधिक।

मेन्स कोण अस्थिर वैश्विक वस्तु कीमतों के बीच हेडलाइन महंगाई के प्रबंधन में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति उपकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131432

सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के दर्शन के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को महत्वपूर्ण बताया

चर्चा में क्यों: CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और 'समाजवादी' (socialist) और 'धर्मनिरपेक्ष' (secular) को प्रस्तावना के दर्शन का अभिन्न हिस्सा माना।

याद रखें

- 42nd Amendment — प्रस्तावना (Preamble) में 'socialist' और 'secular' शब्द जोड़े गए।
- मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1980) — सुप्रीम कोर्ट का केस जिसमें प्रस्तावना (Preamble) में बदलाव को बरकरार रखा गया।
- भारतीय समाजवाद (Indian socialism) — इसे कल्याण और समानता के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित किया गया है।

मेन्स कोण 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में, विधायी संशोधनों के विरुद्ध प्रस्तावना के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131398

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की कार्यवाही रोकने की केंद्र की याचिका खारिज की

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता द्वारा 72,000 करोड़ रुपये के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के खिलाफ दी गई चुनौती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

याद रखें

- ग्रेट निकोबार आइलैंड — ₹72,000 करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की साइट।
- फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act), 2006 — वह कानून जिसके तहत अधिकारों पर कथित तौर पर प्रोजेक्ट द्वारा खतरा है।
- ₹72,000 करोड़ — ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत।

मेन्स कोण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्वदेशी वन अधिकारों के संरक्षण और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/131218

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

ज़ेहनपोरा बौद्ध कॉम्प्लेक्स: अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि कटाव (erosion) के कारण 2,000 साल पुरानी यह साइट 2050 तक 10,122 वर्ग मीटर क्षेत्र खो सकती है।

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट: DGPC और Adani Power ने BOOT मॉडल के तहत 770 MW चामखर्चू-I (Chamkharchhu-I) प्रोजेक्ट के लिए एक शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट (Shareholders Agreement) पर हस्ताक्षर किए।

माउंटेन गार्जियन 2026: भारत और UAE की सेनाओं ने उत्तराखंड में माउंटेन वारफेयर ड्रिल्स और इंटर-ऑपरैबिलिटी एक्सरसाइज शुरू कीं।

एंटी-रैगिंग गाइडलाइन्स: केरल में रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले छात्रों के लिए निष्कासन और तीन साल तक प्रवेश पर रोक अनिवार्य है।

क्लाइमेट डिप्लोमेसी: भारत ने UNFCCC Pre-COP31 बैठकों के दौरान प्रशांत क्षेत्र के भागीदारों को ISRO और तटीय अनुसंधान (coastal research) विशेषज्ञता की पेशकश की।

बेंगलुरु पुलिस: कर्नाटक कैबिनेट ने शहर की पुलिस को पांच कमिश्नरेट (commissionerates) में पुनर्गठित करने को मंजूरी दी है, जिनकी निगरानी चीफ पुलिस कमिश्नर करेंगे।

गंगा जल संधि: 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आलोचना जलवायु-लचीले (climate-resilient) क्लॉज और त्रिपक्षीय दृष्टिकोण (trilateral approach) की कमी के लिए की जाती है।

केरल में ₹10 में मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन, WOMN स्कीम लॉन्च

शहरी विज्ञापन: तेलंगाना ने Core Urban Region (CURE) में टेम्परेरी और हाइपर-लोकल विज्ञापनों को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन्स को मंजूरी दी है।

सुप्रीम कोर्ट की ताकत: चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा तीन नए जजों को शपथ दिलाने के बाद, वर्किंग स्ट्रेंथ (Working strength) 37 तक पहुंच गई।

2036 ओलंपिक की दावेदारी: भारत उन सात देशों में से एक है जो वर्तमान में 2036 Olympics की मेजबानी के लिए बोली लगा रहे हैं।

शिपिंग हमलों: MEA ने ब्लैक सी और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में हुए हमलों की निंदा की, जिससे नाविकों की मौत और उन्हें चोटें आईं।

मानचित्र

चर्चा में स्थान

ग्रेट निकोबार आइलैंड ₹72,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की साइट।

चौबटिया, उत्तराखंड फॉरेन ट्रेनिंग नोड (Foreign Training Node) और एक्सरसाइज माउंटेन गार्जियन 2026 (Exercise Mountain Guardian 2026) का स्थल।

होर्मुज जलडमरूमध्य आमतौर पर प्रतिदिन 125 बड़े कमर्शियल वेसल्स (commercial vessels) से होकर गुजरते हैं।

भोटेकोशी-त्रिशुली नेपाल में बाढ़ से प्रभावित नदी तंत्र।

जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क पक्षियों के रिलीज (release) के लिए साइट।

MEA का दौरा: एस. जयशंकर ने व्यापार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) पर चर्चा करने के लिए घाना, कोट डी आइवोरी और इथियोपिया का दौरा किया।

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

AMCA प्रोपल्शन: Aero-engine क्षमताओं को मजबूत करने के लिए MIDHANI के साथ साझेदारी में HAL Koraput में ₹5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव।

नोबेल पुरस्कार: फ्रांसिस हैलजेन को IceCube न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (Neutrino Observatory) पर उनके कार्य के लिए भौतिकी का 2026 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

बांग्लादेश के लिए DLB पटकाई रवाना, 540 मीट्रिक टन मेथनॉल ले जाएगा

क्वांटम इकोनॉमी: कर्नाटक 2035 तक \$20 बिलियन की क्वांटम इकोनॉमी (quantum economy) बनाने के लिए ₹600 करोड़ का निवेश करेगा और एक सिंगल-विंडो इंटरफेस (single-window interface) स्थापित करेगा।

गल्फ तेल निर्यात: समुद्री सुरक्षा घटनाओं के बावजूद, सितंबर में यह पूर्व-युद्ध स्तर के 81 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच गया।

पानी की कटौती: महाराष्ट्र में 265 तालुकाओं में सूखे के कारण 16 अक्टूबर 2026 से सभी स्थानीय निकायों (local bodies) पर 10% वॉटर कट (water cut) लागू किया जाएगा।

बोरवेल सुरक्षा अभियान: बच्चों की मौतों को रोकने के लिए कर्नाटक की पहल असुरक्षित खुले बोरवेल (borewells) की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए।

INR कनेक्ट: रबर टैपर्स (rubber tappers) और प्लांटेशन मालिकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए रबर बोर्ड (Rubber Board) की एक नई पहल।

पर्यटन को इंडस्ट्रियल स्टेटस: केरल ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 अक्टूबर, 2026 तक पर्यटन क्षेत्र (tourism sector) को इंडस्ट्रियल स्टेटस (industrial status) देने का प्रस्ताव दिया है।

आने-जाने का खर्च: शहरी श्रमिक आवाजाही (commuting) पर मासिक ₹1,044 खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए यह खर्च ₹612 है।

RAMP स्कीम: MSMEs को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (Intellectual Property) और कमर्शियलाइजेशन (Commercialization) में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय MSME मंत्रालय की पहल।

1 HSL के अपग्रेड किए गए Slipway-4 पर बनने और लॉन्च होने वाले जहाजों की अधिकतम डेडवेट टनेज (deadweight tonnage) क्षमता क्या है?

- (a) 50,000 टन (b) 45,000 टन
(c) 30,000 टन (d) 60,000 टन

2 एयरोस्पेस और डिफेंस मैनुफैक्चरिंग के लिए प्रस्तावित निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. HAL, AL-31FP के उत्पादन के लिए ₹500 करोड़ निवेश करने की योजना बना रहा है।
2. दूसरी शक्ति इंजन लाइन को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3. AMCA प्रोपल्शन के लिए प्रस्तावित निवेश ₹5,000 करोड़ है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3 भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति (monetary policy) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बेंचमार्क रिपर्चेज रेट (repurchase rate) को बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने की उम्मीद है।
2. तेल की कीमतें वर्तमान में \$50 प्रति बैरल से नीचे चल रही हैं।
3. वर्तमान में महंगाई के 3 प्रतिशत से नीचे रहने की उम्मीद है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

4 प्रस्तावना (Preamble) और 42nd Amendment के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोर्ट ने भारतीय समाजवाद (Indian socialism) को लाभ और प्रतिस्पर्धा (competition) के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित किया।
2. 42nd Amendment द्वारा प्रस्तावना (Preamble) में 'socialist' और 'secular' शब्द जोड़े गए।
3. सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Minerva Mills v. Union of India) केस में प्रस्तावना (Preamble) में बदलाव को बरकरार रखा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

5 ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट (Great Nicobar Island Project) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आरोप लगाया गया है कि यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act), 1998 के लिए खतरा पैदा करता है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
3. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹72,000 करोड़ है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

मेन्स अभ्यास

आज एक उत्तर लिखें

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत के समुद्री क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' पहल और समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में, एचएसएल (HSL) जैसी घरेलू जहाज निर्माण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के योगदान का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ · हर रविवार साप्ताहिक · हिंदी और अंग्रेज़ी · मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh · satyadheesh.in/upsc/reports

कोई गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक या फॉर्मेट चाहिए? हमें लिखें, हम हर मेल पढ़ते हैं:

contact@satyadheesh.in

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।